



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022020-215961
CG-DL-E-06022020-215961

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2020/माघ 11, 1941

No. 32]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2020/MAGHA 11, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरुआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2020

(मामला संख्या ओआई-34/2019)

विषय: यूरोपीय संघ, सउदी अरब, चाइनीज ताइपेई और संयुक्त अरब अमीरात से टोल्यूइन डी-आइसोसाइनेट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/43/2019-डीजीटीआर.—1. मै. गुजरात नर्मदा वैली फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमि. (जिसे यहां "आवेदक" कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसरण में यूरोपीय संघ (ईयू), सउदी अरब, चाइनीज ताइपेई और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) (जिन्हें यहां "संबद्ध देश" कहा गया है) से टोल्यूइन डी-आइसोसाइनेट, जिसे टीडीआई के रूप में भी जाना जाता है (जिसे यहां "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और पाटनरोधी शुल्क लागू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे यहां "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने दावा किया है कि यूरोपीय संघ, सउदी अरब, चाइनीज ताइपेई और संयुक्त अरब अमीरात से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और यूरोपीय संघ, सउदी अरब, चाइनीज ताइपेई और संयुक्त अमीरात के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "टोल्यूइन डी-आइसोसाइनेट" (टीडीआई) 80:20 के अनुपात में आइसोमर सामग्री है। टोल्यूइन डी-आइसोसाइनेट $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_3(\text{NCO})_2$ फार्मूले सहित एक आर्गेनिक कम्पाउंड है। छह संभव आइसोमर्स के दो आइसोमर्स व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हैं : 2,4-टीडीआई (सीएस: 584-84-9) और 2,6-टीडीआई (सीएस: 91-08-7)। 2,4 – टीडीआई शुद्ध अवस्था में उत्पादित किए जाते हैं, किंतु टीडीआई का प्रायः क्रमशः 2,4 और 2, 6 आइसोमर्स के 80/20 और 65/35 मिश्रण के रूप में विपणन किया जाता है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (80:20) के अनुपात में आइसोमर सामग्री वाले टीडीआई से संबंधित है। अन्य सभी ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर हैं।

4. इस उत्पाद को कोड 2929 10 20 के तहत अध्याय शीर्ष 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर बाधित नहीं है।

समान वस्तु

5. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तुएं, जो भारत में पाटित की जा रही हैं, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। यह कहा गया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित टीडीआई भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, तथा विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी (पूरे विश्व में इसके उत्पादन के लिए कोई अन्य ज्ञात प्रौद्योगिकी नहीं है), कार्य और प्रयोगों, उत्पाद विशिष्टताओं, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की शर्तों में तुलनीय हैं। तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से ये दोनों प्रतिस्थापनीय हैं। प्रयोक्ता ने इन दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है और कर रहे हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजन हेतु, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग

6. आवेदन मैसर्स गुजरात नर्मदा वैली फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमि. द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने दावा किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देश से पी यू सी का आयात किया है, न ही वे संबद्ध देश में पीयूसी के किसी निर्यातक या उत्पादक से अथवा भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) में अंतर्निहित प्रावधानों की शर्तों में घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उनकी ओर से प्रस्तुत किया गया है।

कथित पाटन का आधार

सामान्य मूल्य

7. ई यू के मामले में, आवेदक ने ई यू क्षेत्र की घरेलू कीमतों पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का दावा किया है। इस प्रयोजन हेतु आवेदक ने ऐसे सदस्य देशों की संबद्ध वस्तुओं के निर्यात आंकड़े अधिप्राप्त किए हैं जिनके पास संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की सुविधा है अर्थात् जर्मनी और हंगरी। संगत सूचना इन देशों से बाकी ई.यू. सदस्य देशों को की गई विक्री को दर्शाने वाले ई.यू. के सीमाशुल्क आंकड़ों का प्रयोग करते हुए प्राप्त की गई है। चूंकि, संबद्ध वस्तुएं जर्मनी और हंगरी में उत्पादित की जाती हैं, इसलिए इन दो देशों से बाकी यूरोपीय संघ को किए गए निर्यातों को प्राधिकारी द्वारा कमीशन, बैंक प्रभारों, पत्तन और हैंडलिंग प्रभारों का समायोजन करने के पश्चात यूरोपीय संघ में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य के रूप में लिया गया है।

8. सउदी अरब, चाइनीज ताइपेई और संयुक्त अरब अमीरात के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, आवेदक ने दावा किया है कि वे इन तीनों देशों में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों से संबंधित सूचना प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए, लाभ के लिए उचित परिवर्द्धनों के सहित भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत का निर्माण करके सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है।

निर्यात कीमत

9. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत की संगणना डी जी सी आई एंड एस के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर की है। समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों और पत्तन व्ययों के कारण समायोजन किए गए हैं।

10. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखानागत स्तर पर तुलना की गई है, जो संबद्ध देशों से पीयूसी के संबंध में सकारात्मक पाटन मार्जिन दर्शाते हैं। इसके पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पी यू सी पाटित किए जा रहे हैं।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

11. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए प्रयोग किया गया है। आवेदक ने कुल रूप में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में, कीमत कटौती और कीमत दमन के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि कीमत से कम कीमत पर बिक्री और घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत पर संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप, लाभों, नियोजित पूंजी पर प्राप्ति और नकदी प्रवाह के संबंध में इसके निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि की उल्लेखनीय दर, संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं की महत्वपूर्ण क्षमताओं और घरेलू बिक्री कीमतों पर आयात कीमतों के ह्रासात्मक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को क्षति का खतरा बढ़ा है। एक पाटनरोधी जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही क्षति के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

12. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत पुष्टि किए गए लिखित आवेदन के आधार पर और नियमावली पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं संतुष्ट होने तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क के अनुसरण में, प्राधिकारी, एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि का निर्धारण करने, जो यदि लागू की जाती तो, घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होती, एक जांच की शुरुआत करते हैं।

संबद्ध देश

13. वर्तमान जांच में संबद्ध देश यूरोपीय संघ, सउदी अरब, चाइनीज ताइपेई और संयुक्त अरब अमीरात हैं।

जांच की अवधि (पी ओ आई)

14. आवेदक ने जांच की अवधि (जिसे यहां पीओआई भी कहा गया है) 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2019 (6 महीने) प्रस्तावित की है। प्राधिकारी ने भी पी ओ आई 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2019 (6 महीने) के रूप में विचारित की है। क्षति जांच अवधि में 2016-17, 2017-18, 2018-19 और पीओआई की अवधि शामिल होगी।

प्रक्रिया

15. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में यथानिर्धारित सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देशों में निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, विचाराधीन उत्पाद से संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सभी संगत सूचना दायर कर सकें।

17. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र और तरीके में जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकते हैं। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किए जाएं:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
व्यापार उपचार महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

18. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार से यह अनुरोध है कि वह अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध करायें।

समय-सीमा

19. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में दी जानी चाहिए ताकि वह नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी को पहुँच जाए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त नियमावली की व्याख्या के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाए जाने संबंधी सूचना उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी जिसको वह प्राधिकारी द्वारा भेजी गई थी अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा सूचना अपूर्ण प्राप्त होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं।

20. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हितों की प्रकृति सहित) सूचित करें और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

21. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्ट/उससे संलग्न अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को, यदि उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया गया है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में दायर करना अपेक्षित है:

- i. गोपनीय के रूप में चिन्हित एक सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि), और
- ii. अगोपनीय के रूप में चिन्हित दूसरा सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि)।

22. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिन्हित होने चाहिए। इस प्रकार के चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे। दोनों रूपांतरों की सॉफ्ट प्रतियां भी प्रत्येक के चार (4) सेटों की हार्ड प्रतियों के साथ प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होंगी।

23. गोपनीय रूपांतर में वह सभी सूचना होगी जो प्रकृति से गोपनीय और/अथवा अन्य सूचना है जिसको सूचना देने वाला गोपनीय होने का दावा करता है। जिस सूचना को प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के संबंध में अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस सूचना के संबंध में सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ सही कारण का विवरण प्रदान करें कि उस सूचना का प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।

24. अगोपनीय रूपांतर को गोपनीय सूचना के साथ अधिमानतः उस सूचना के आधार पर सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक आउट (यदि सूचीकरण व्यवहार्य नहीं है) तथा सारांश का प्रदर्श होना अपेक्षित है जिसके आधार पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार की उपयुक्त समझ देने के लिए

पर्याप्त ब्यौरे में होने चाहिए। तथापि, अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह दर्शा सकते हैं कि यह सूचना सारांश के लिए संवेदनशील नहीं है; सारांश क्यों संभव नहीं है, इसका एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप दिया जाना चाहिए।

25. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा रद्द कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं हैं अथवा यदि सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसे प्रकट करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता तो वे उसकी अनदेखी कर सकते हैं।

26. किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में अच्छे कारण के विवरण के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

27. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर तथा दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

28. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

29. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना देने से इंकार करता है अथवा अन्यथा उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को जैसा भी वे उचित समझें सिफारिश कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस , भल्ला अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2020

Case No. (O.I.) 34/2019

Subject: Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of Toluene Di-Isocyanate from European Union, Saudi Arabia, Chinese Taipei and United Arab Emirates.

F. No. 6/43/2019-DGTR.—1. M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (hereinafter also referred to as “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (herein referred to as the “Authority”) in accordance with Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (herein referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein also referred to as the “Rules”) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on imports of Toluene Di-Isocyanate also known as TDI (hereinafter referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC” from European Union (EU), Saudi Arabia, Chinese Taipei and United Arab Emirates(UAE)(hereinafter referred to as “subject countries”).

- The Applicant has claimed that the injury to the domestic industry is being caused due to dumped imports from European Union, Saudi Arabia, Chinese Taipei and United Arab Emirates and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from European Union, Saudi Arab, Chinese Taipei and United Arab Emirates.

Product under consideration

- The product under consideration in the present investigation is “Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20”. Toluene di-isocyanate (TDI) is an organic compound having formula CH₃C₆H₃(NCO)₂. Two of the six possible isomers are commercially important: 2,4-TDI (CAS: 584-84-9) and 2,6-TDI (CAS: 91-08-7). 2,4-TDI is produced in the pure state, but TDI is often marketed as 80/20 and 65/35 mixtures of the 2,4 and 2,6 isomers respectively. The product under

consideration in the present investigation concerns TDI having isomer content in the ratio of (80:20). All other grades are beyond the scope of product under consideration.

4. The product is classified under the Chapter Heading 29 under the code 2929 10 20. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

Like article

5. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. It has been stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the Applicant and those exported from subject countries. The Applicant has claimed that TDI produced by the domestic industry and imported from subject countries is comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology (there is no other known technology for production world over), functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. For the purpose of present investigation, the subject goods produced by the Applicant are being treated as 'like article' of the subject goods imported from the subject countries.

Domestic industry

6. The application has been filed by M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited. The Applicant is the sole producer of the subject goods in India. The Applicant has claimed that neither they have imported the PUC from the subject countries nor they are related to any exporter or producer of PUC in the subject countries or any importer of the PUC in India. On the basis of the information available, the Authority notes that the application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

Basis for Alleged Dumping

Normal value

7. In case of EU, the Applicant has claimed normal value by considering the domestic prices in EU region. For this purpose, the Applicant has procured the export data of subject goods of the member countries which have production facilities of subject goods i.e. Germany and Hungary. The relevant information has been obtained using customs data of EU showing sales from these countries to rest of the EU member countries. Since the subject goods are produced in Germany and Hungary, therefore exports from these two countries to the rest of the European Union have been taken as the normal value of the subject goods in European Union after making adjustments for commission, bank charges, port and handling charges by the authority.
8. For the purpose of determining the normal value for Saudi Arabia, Chinese Taipei and United Arab Emirates, the applicant have claimed that they were not able to fetch information relating to the prices of the subject goods in the three countries. Therefore, the normal value has been determined by constructing the cost of production of subject goods in India along with reasonable additions for profit.

Export Price

9. The Authority has computed the export price for the subject countries based on the DGCI&S transaction wise import data. Adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges and port expenses.
10. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows positive dumping margin in respect of the PUC from the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the PUC are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

Injury and Causal Link

11. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price depression and price suppression. The applicant has claimed that its performance has been adversely impacted in respect of profits, return on capital employed, and cash flow, as a result of increase in imports of subject goods at a price below the selling price and non-injurious price for the domestic industry. The Applicant has also claimed that there is a further threat of injury to the domestic industry in view of significant rate of increase in imports from the subject countries, significant capacities of subject goods in subject countries and depressing effect of import prices on domestic selling prices. There is sufficient prima facie evidence of injury being suffered by domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an anti-dumping investigation.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

12. On the basis of the duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury and in accordance with the Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Subject countries

13. The subject countries in the present investigation are European Union, Saudi Arabia, Chinese Taipei and United Arab Emirates.

Period of Investigation (POI)

14. The Applicant proposed the Period of Investigation (hereinafter also referred to as POI) 1st April 2019 to 30th September 2019 (6 months). The Authority has also considered the POI as 1st April 2019 to 30th September 2019 (6 months). The injury investigation period will cover the period 2016-17, 2017-18, 2018-19 and POI.

Procedure

15. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submissions of information

16. The known exporters in the subject countries, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the PUC and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below
17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. The information/ submission may be submitted to:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5 Parliament Street, New Delhi – 110001

18. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time limit

19. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.
20. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

21. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
- i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
 - ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

22. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each.
 23. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
 24. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
 25. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
 26. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
 27. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.
- Inspection of public file**
28. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non- confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.
- Non-cooperation**
29. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority